had Stock Exchange. Hence no information regarding public issue has been furnished.

(b) and (c) The office of the Controller of Capital Issues stands abolished with effect from 29-5-92. A scarch and seizure operation was acrruiet cut in August, 1992 by the Income Tax Department on the Shyam Bhatia Group, in the course of which assets of the value of Rs. 16.22 crores and incriminating documents were seized.

राज्यों में चुनाव

1623. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के किन-किन राज्यों में इस वर्ष चुनाव होने है तथा कौन-कौन सी तारीखों को होन हैं ;

(ख) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर में मतदाताओं की संशोधित मतदाता सूची तैयार कर ली है; और

(ग) देश के उन निर्वाचन क्षेत्रों के नाम क्या है जहां लोक सभा की सीटें रिक्त पड़ी है तथा इन निर्वाचन क्षेत्रों में कब तक निर्वाचन कराए जाने की संभावना है ;

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मणिपुर, और उड़ीसा राज्यों म पहले ही निर्वाचन कराए जा चुके हैं। बिहार राज्य में निर्वाचन कार्य चल रहा है और मतदान का अगला चक्र 25 मार्च, 1995 के लिए नियुत किया गया है। 1995 में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा के लिए कोई अन्य साधारण निर्वाचन नहीं होते है।

(ख) निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में निर्वाचक-नामावलियों के पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है और नामावलियों का अंतिम रूप से प्रकाशित 29 मार्च, 1995 को किया जाना नियत किया गया है।

(ग) 20 (जिनमें जम्मू-कश्मीर राज्य के 6 संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र भी है) 24-पूर्निया संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में 20 मार्च, 1995 को पुर्नमतदान हुआ है। निर्वाचन आयोग ने शेष संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों में निर्वाचन कराने के लिए अभी तक कोई कार्यक्रम नियत नहीं किया है।

भोपाल और रायपुर में उच्च न्यायालय की न्यायपीठें

1624. **श्री राघव जी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से मध्य प्रदेश में भोपाल और रायपुर में उच्च-न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने का कोई सुझाव प्राप्त हुआ है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन दोनों स्थानों पर उच्च-न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने के संबंध में सरकार की नीति क्या है तथा उन न्यायपीठों की स्थापना में हो रहे विलंब के कारण क्या है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश उच्च-न्यायालय की न्यायपीठें रायपुर और भोपाल में, स्थापित किए जाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से, राज्य पुर्नगठन अधिनियम, 1956 की धारा 51(2) के निबंधनों के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करके कोई विनिर्दिष्ट, पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। सरकार द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य स्थान से भिन्न स्थानों पर उच्च न्यायालय की न्यायपीठें स्थापित करने की बात, अभी तक कोई नीतिगत विनिश्चय नहीं किया गया है।